[2015] 5 एस.सी.आर. 846

चारु किशोर मेहता

बनाम

संयुक्त चैरिटी आयुक्त, ग्रेटर बॉम्बे क्षेत्र एवं अन्य.

(सिविल अपील संख्या 2819/2015)

मार्च 12, 2015

[वी. गोपाल गौडा और सी. नागप्पन, जे.जे.]

बॉम्बे पब्लिक न्यास अधिनियम, 1950-धारा 41 डी- तहत आवेदन-सार्वजनिक विश्वासों में से एक के द्वारा- अन्य ट्रस्टियों (प्रतिवादी संख्या 2 से 9) के खिलाफ जिसमें एक मृत न्यासी भी शामिल है -उनकी न्यासीशिप से बर्खास्तगी की मांग और अकर्मण्यता और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए-संयुक्त चैरिटी आयुक्त द्वारा आवेदन खारिज किया गया जिसमें यह कहा गया कि 7 ट्रस्टियों को छूट दी जा सकती है क्योंकि उन्हें केवल अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व मृत न्यासी (प्रबंध न्यासी) के पक्ष में करने में लापरवाह माना जा सकता है - उच्च न्यायालय द्वारा आदेश की पुष्टि की गई - अपील पर, यह माना गया: निचली अदालतों ने उचित और न्यायसंगत तरीके से ट्रस्टियों (प्रतिवादियों) को छूट दी - प्रबंध न्यासी के पक्ष में प्रतिवादी-ट्रस्टियों द्वारा शक्तियों और कार्यों का प्रतिनिधित्व इसलिए स्वीकार्य था क्योंकि न्यास के दस्तावेज में इसके लिए प्रावधान था - ट्रस्ट्स - न्यास अधिनियम, 1882 - धारा 46 और 47।

अपील खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. न्यास की न्यास डीड के खंड 9 और 11 (एच) न्यास के ट्रस्टियों द्वारा शक्तियों और कार्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रावधान करते हैं, यह एक या अधिक मौजूदा ट्रस्टियों को उनके बीच से नियुक्त करके सभी ऐसी शक्तियों और कार्यों का निर्वहन करने के लिए जैसा कि वे उचित और समुचित समझें। 30.8.2001 के प्रस्ताव द्वारा, न्यासी, प्रतिवादी संख्या 2 से 9 तक जिसमें अपीलकर्ता भी शामिल है, उन्होंने अपनी शक्तियों और कार्यों को मृत न्यासी को न्यास के मामलों को संभालने के लिए सौंप दिया था। इस प्रकार, न्यास डीड के खंड 9 और 11 (एच) स्पष्ट रूप से यह दिखाते हैं कि न्यास के ट्रस्टियों के शक्तियों और कार्यों को अन्य न्यासी या ट्रस्टियों को उनकी ओर से कार्य करने के लिए ऐसे प्रतिनिधित्व के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। [पैराग्राफ 17, 18 और 19] [857-एफ; 858- बी ई; 859-एफ-जी]

जे.पी. श्रीवास्तव और संस (प्रा.) लि. बनाम ग्वालियर शुगर कं. लि. (2005) 1 एससीसी 112: 2004 (5) सप्लीमेंट एस.सी.आर. 648 - पर निर्भर किया गया।

2. न्यास अधिनियम, 1882 की धाराओं 46 और 47 के आधार पर दी गई याचिका, जिसका आशय यह है कि न्यासी अपना पद त्याग नहीं सकता जिसमें उसे अपने कर्तव्यों और कार्यों को निर्वहन करना आवश्यक

होता है और वह इसे किसी सह-न्यासी को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता, यह जनहित के चैरिटेबल न्यास पर लागू नहीं होता है। [पैराग्राफ 21] [861-ई]

थयारम्मल बनाम कनकम्मल और अन्य (2005) 1 एससीसी 457: 2004 (6) सप्ली. एस.सी.आर. 734 - पर निर्भर किया गया।

3. संयुक्त चैरिटी आयुक्त ने सही रूप से यह माना है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 9 का दोष सिद्ध नहीं होता है और यह भी माना है कि वे केवल अपनी शक्तियों और कार्यों को प्रबंधन न्यासी को प्रतिनियुक्ति करने के लिए लापरवाह हैं, लेकिन उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं होते क्योंकि वे कथित लेन-देन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, अतः, उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में उनकी मिलीभगत नहीं है। आयुक्त का यह निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और सबूतों पर आधारित है, इसलिए, उसने उन्हें दायित्व से सही ढंग से मुक्त किया है और अधिनियम की धारा 41 डी के तहत उन पर दंड नहीं लगाया है, क्योंकि उसने अपनी शक्ति का उपयोग उचित और निष्पक्ष तरीके से किया है और इसलिए, यह कहना नहीं हो सकता कि यह मनमाना और अनुचित स्वभाव का है। [पैराग्राफ 23] [864-ई-एचएचजे]

शेख अब्दुल कयूम और अन्य बनाम मूला अलीभाई और अन्य (1963) 3 एस.सी.आर. 623; जे.पी. श्रीवास्तव एंड संस (प्रा.) लिमिटेड

बनाम ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड (2005) 1 एससीसी 172: 2004 (5) सप्ली. एस.सी.आर. 648; डी. गोपालस्वामी मुदलियार बनाम सुब्रमण्य पिल्लै और अन्य (1942) 1 एम.एल.जे. 272; लाला मन मोहन दास बनाम जानकी प्रसाद और अन्य ए.आई.आर. (32) 1945 प्राइवी कौंसिल 23 - विशिष्ट।

**न्यायिक निर्णय संदर्भ**

एआईआर (32) 1945 प्राइवी काउंसिल 23 – विशिष्ट - पैराग्राफ 10, 13

(1963) 3 एस.सी.आर. 623 विशिष्ट पैराग्राफ 13

2004(5) सप्ली. एस.सी.आर. 648 पर निर्भर किया गया। पैराग्राफ 19

2004 (6) सप्ली. एस.सी.आर. 734 पर निर्भर किया गया। पैराग्राफ 21

(1942) 1 एम.एल.जे. 272 विशिष्ट पैराग्राफ 24

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2819/2015

बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा डब्ल्यू. पी. संख्या 9501/2009 में लैटर पेटेंट अपील संख्या 268/2010 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 1.12.2010 से उत्पन्न।

वी. गिरी, अजय भार्गव, वनिता भार्गव, राज पटेल, नितिन मिश्रा, (खैतान एंड कंपनी के लिए) अपीलकर्ता की ओर से।

डॉ. राजीव धवन, शंकर चिल्लर्गे, एजीए, अनिरुद्ध पी. मायी, बालाजी श्रीनिवासन, मिहिर मोदी, संदीप गुप्ता, तुषार गुप्ता, जेसल शाह, (काशर एंड कंपनी के लिए), प्रतीक एस., रंजीता रोहतगी, गौरव अग्रवाल प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया-

**वी. गोपाला गौडा, न्यायाधीश.**

1. अनुमति अनुदत्त की गई।

2. यह अपील अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय मुंबई के विवादास्पद निर्णय और दिनांक 01.12.2010 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जो कि पत्र पेटेंट अपील संख्या 268 वर्ष 2010 (संक्षिप्त में "एल.पी.ए.") में रिट याचिका संख्या 9501 वर्ष 2009 में था, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई एल.पी.ए. को खारिज कर दिया और दिनांक 02.03.2010 को पारित किये गए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश को बरकरार रखा।

3. इस अपील में पक्षों की ओर से उठाए गए प्रतिस्पर्धी कानूनी तर्कों पर विचार करने के उद्देश्य से और यह जांचने के दृष्टिकोण से कि क्या इस अदालत को उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, आवश्यक तथ्य यहां संक्षेप में बताए गए हैं:

यहाँ अपीलकर्ता लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल न्यास (संक्षेप में "न्यास") के स्थायी न्यासी हैं, जो कि पंजीकृत न्यास विलेख की शर्तों के अनुसार एक सार्वजनिक पंजीकृत न्यास है और बॉम्बे पब्लिक न्यास अधिनियम, 1950 (संक्षेप में "अधिनियम") के प्रावधानों के अंतर्गत शासित है। प्रतिवादी संख्या 2 से 9 उक्त न्यास के न्यासी हैं, साथ ही अब स्वर्गीय विजय मेहता भी हैं, जो संबंधित समय के दौरान न्यास के प्रबंध न्यासी थे। प्रतिवादी संख्या 2 से 9 उक्त न्यास के न्यासी हैं, साथ ही अब स्वर्गीय विजय मेहता भी हैं, जो संबंधित समय के दौरान न्यास के प्रबंधन न्यासी थे। उन्होंने वर्ष 2001 से 2006 तक न्यास की संपत्तियों का गबन भी किया है और अनुचित ढंग से उनका उपयोग किया है। अपीलकर्ता द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने करोड़ों रुपये की न्यास की धनराशि को भी दुरुपयोग किया है और गंभीर दुर्व्यवहार किया है।

4. अपीलकर्ता को जब वर्ष 2006 में इस तथ्य का पता चला, तो उसने ज्वाइंट चैरिटी आयुक्त (संक्षेप में "जेसीसी.") के समक्ष अधिनियम की धारा 41D के तहत आवेदन संख्या 17/2006 दायर किया, जिसमें उक्त प्रतिवादी संख्या 2 से 9 सहित स्वर्गीय विजय मेहता के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाए गए और यह आरोप लगाया गया कि वे उनके द्वारा किए गए अकर्मण्यता और दुर्व्यवहार के कार्यों के लिए न्यास की न्यासीशिप से बर्खास्तगी के लिए जिम्मेदार हैं, यह दलील देते हुए कि उन्होंने अधिनियम की धारा 36A के तहत प्रदान की गई उनकी कार्य और कर्तव्यों को त्याग

दिया है, उस न्यास में न्यासी के रूप में उनकी स्वीकृति के बाद जैसा कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 46 और 47 के तहत प्रदान किया गया है, जो वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति के लिए लागू होता है।

उक्त आवेदन के आधार पर, JCC ने प्रतिवादी संख्या 2 से 9 (मूल प्रतिवादी संख्या 1 से 8) और स्वर्गीय विजय मेहता (मूल प्रतिवादी संख्या 9) के खिलाफ संयुक्त रूप से 8 गंभीर संगीन आरोप तय किए।

5. JCC ने अपने आदेश दिनांक 25.9.2009 को, वर्तमान मामले में पक्षों को अवसर प्रदान करने के बाद, आरोपों पर अपनी निष्कर्ष दर्ज किया और पाया कि प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए हैं, सिवाय आरोप संख्या 4 के जो कि स्वर्गीय विजय मेहता के खिलाफ था। हालांकि, जेसीसी ने प्रतिवादी नंबर 2 से 9 के खिलाफ आवेदन को खारिज कर दिया और उन्हें यह कहते हुए बरी कर दिया कि वे मृतक विजय मेहता के पक्ष में न्यास के न्यासी के रूप में अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को सौंपने में अंधा विश्वास करने में लापरवाही कर रहे हैं। । अतः उनके द्वारा उनके विरूद्ध प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता ने जेसीसी द्वारा दर्ज किए गए उक्त निष्कर्षों और कारणों से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका संख्या 9501/2009 दायर की, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 02.03.2010 के तहत रिट याचिका को खारिज कर दिया।

6. इसके बाद, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में एलपीए संख्या 268/2010 को दायर किया, जिसे खंड पीठ ने भी एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई खोजों के आधार पर खारिज किया और यह निर्णय दिया कि जेसीसी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के खिलाफ तय किए गए आरोप सिद्ध हो गए थे। हालाँकि, चूँकि आरोप संख्या 4 को छोड़कर, वर्ष 2001 से 2006 तक के लेनदेन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए यह माना गया है कि मृतक विजय मेहता दोषी हैं और इसके अलावा, जेसीसी ने माना है कि न्यास के संकल्प दिनांक 30.8.2001 के तहत न्यास डीड के खंड 9 और 11 (एच) के अनुसार मृतक विजय मेहता को अपनी शक्तियां और कार्य सौंपने में प्रतिवादी संख्या 2· से 9 के खिलाफ आरोप कायम हैं। स्थापित किया गया और उनके खिलाफ साबित किया गया लेकिन उन्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अपीलकर्ता स्वयं उपरोक्त संकल्प के हस्ताक्षरकर्ता थे। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने, जिसका आदेश दिनांक 1.12.2010 को हुआ, निर्णय लिया कि वे उन्नत अधिवक्ता न्यायधीश द्वारा 2.3.2010 को दिये गए आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने यह निष्कर्ष किया कि इस निर्णय को उचित माना जा सकता है उनके ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता स्वयं उपर्युक्त प्राधिकृति के एक हिस्सा थीं, जिसमें स्वर्गीय विजय मेहता को न्यास के प्रबंधन न्यासी के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, उनके द्वारा प्रस्ताव को रद्द करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया क्योंकि उन्होंने अपने आचरण को सही ठहराने के

लिए जेसीसी के समक्ष गवाह बॉक्स में भी प्रवेश नहीं किया था कि वह उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं जिसमें मृतक विजय मेहता को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। अन्य ट्रस्टियों द्वारा न्यासी जो वर्तमान अपील में प्रतिवादी संख्या 2 से 9 हैं। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता ने उस समय प्रबंध न्यासी के रूप में अपने कामकाज पर कोई आपत्ति नहीं जताई जब सभी शक्तियां उसे सौंपी जा रही थीं और पाया कि याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष गंभीरता से नहीं लड़ा गया था और अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया।

7. उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता द्वारा जेसीसी और उच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेशों को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान अपील दायर की गई है और ऐसा पारित करने का अनुरोध किया गया है। विभिन्न तथ्यों और कानूनी तर्कों का आग्रह करते हुए इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह न्यायालय उचित और उचित समझे जाने वाले आदेश दे सकता है।

8. श्री वी. गिरी, अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलकर्ता प्रासंगिक अवधि के दौरान अर्थात 30.3.2002 से 1.4.2007 तक, और विशेष रूप से 30.8.2001 और 19.7.2002 को आयोजित मीटिंग्स में उपस्थित नहीं था, जिस तथ्य की गवाही श्री किशोर के. मेहता (मूल प्रतिवादी संख्या 10 से पहले जेसीसी में) ने दी है, जो कि

जेसीसी के समक्ष की गई कार्यवाही में अपीलकर्ता के पति हैं। तथापि, जेसीसी ने गलती से प्रतिवादी संख्या 2 से 9 को निर्दोष ठहराया है और मृतक विजय मेहता को ही हटाने के लिए दंड लगाया है, अधिनियम की धारा 41 डी के प्रावधान के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए यद्यपि प्रतिवादी संख्या 2 से 9 को भी न्यास संपत्तियों के संबंध में गैर-कर्तव्यपालन और दुर्व्यवहार के आरोप में दोषी पाया गया था। इसलिए, जेसीसी द्वारा अधिनियम की धारा 41 डी के प्रावधान के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग विधिक दृष्टिकोण से गलत है क्योंकि उसने उक्त प्रावधान के अधीन प्रदान की गई दंडात्मक कार्रवाई के अनुसार उनके विरुद्ध कोई दंड नहीं लगाया है।

9. इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि मृतक विजय मेहता की प्रतिवादी संख्या 2 से 9 की ओर से न्यास के प्रबंध न्यासी के रूप में नियुक्ति को न्यास के मूल कार्यों के त्याग के रूप में नहीं समझा जा सकता क्योंकि न्यासीयों को न्यास के मामलों को उसी प्रकार सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना चाहिए जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति समझदारी से करेगा। उन्होंने उपरोक्त विधिक तर्कों के समर्थन में अधिनियम की धारा 36ए पर दृढ़ भरोसा जताया है और आगे यह तर्क दिया है कि 1882 के भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत उपबंध, जो उपबंध इस बात की पुनरावृत्ति करता है कि एक न्यासी को न्यास संपत्तियों के साथ उसी सावधानी से निपटना चाहिए जैसे कि एक

सामान्य व्यक्ति उस संपत्ति के साथ निपटेगा, मानो वह संपत्ति उसकी अपनी हो। भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 46 और 47 के अनुसार, न्यासी उस पद का परित्याग नहीं कर सकते जिसके अंतर्गत उन्हें अपने कर्तव्यों और कार्यों का पालन करना अनिवार्य है, और वे अपनी जिम्मेदारियों को किसी सह-न्यासी को हस्तांतरित भी नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि न्यास की संस्था इसकी अनुमति दे।इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जेसीसी द्वारा विवेकाधीन शक्तियों का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया गया और प्रतिवादी संख्या पर अधिनियम की धारा 41 डी के तहत दंड नहीं लगाया गया। कानून की नजर में 2 से 9 गलत है| उनके किस आदेश को उच्च न्यायालय ने ग़लती से आक्षेपित निर्णय और आदेश में अनुमोदित कर दिया है और इसलिए अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उसे रद्द करने की प्रार्थना की है। इसके अलावा, प्रस्तुत करने के दौरान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपीलकर्ता की ओर से दिनांक 06.01.2015 को एक हलफनामा पेश किया था, जिसमें 2000-2007 की अवधि के लिए न्यास की मिनट्स बुक को उनके तर्क के समर्थन में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उक्त मिनट्स बुक का निर्माण उनके द्वारा उन तथ्यों को उजागर करने के लिए किया गया है कि यदि उन्हें वैसे ही पढ़ा जाए जैसे वे खड़े हैं, तो यह स्पष्ट रूप से और मुख्य रूप से प्रदर्शित होगा कि जेसीसी से पहले मूल प्रतिवादी नंबर 1 से 8 तक के दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के बारे में सकारात्मक

रूप से जागरूक थे। मृतक प्रबंध न्यासी विजय मेहता को जिसके लिए उन्हें न्यास की न्यासीशिप से बर्खास्त कर दिया गया था।

10. इन परिस्थितियों में, जेसीसी प्रतिवादी संख्या 2 से 9 को यह कहकर बरी नहीं कर सकती थी कि वे न्यास के मामलों में मृतक विजय मेहता के कुकर्मों से अनभिज्ञ थे क्योंकि वे हस्तक्षेप कर सकते थे और न्यास को कोई और नुकसान से बचाने के लिए सुधारात्मक कदम उठा सकते थे। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने लाला मन मोहन दास बनाम जानकी प्रसाद और अन्य[(1)] के मामले में प्रिवी काउंसिल के फैसले पर मजबूत भरोसा जताया है। 1 अपने कानूनी तर्क के समर्थन में यह दिखाने के लिए कि कानून न्यासी द्वारा किसी अन्य न्यासी के पक्ष में शक्तियों और कार्यों के प्रतिनिधिमंडल की अनुमति नहीं देता है, आवश्यकता के मामलों को छोड़कर या लाभार्थी की सहमति से या न्यास डीड के प्राधिकारी के साथ और यह भी दिखाने के लिए कि वहाँ केवल कुछ कार्यों का ही प्रत्यायोजन है। हालाँकि, सभी कार्यों और सभी शक्तियों का प्रत्यायोजन पुरुषों के एक नए समूह के पक्ष में उनके परित्याग से कम नहीं है और यह भी दर्शाता है कि एक न्यासी का कार्य एक सह-न्यासी की मंजूरी और अनुमोदन के साथ किया जा सकता है। दोनों का कृत्य माना जाएगा। इसलिए, जेसीसी द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग न करना और अधिनियम की धारा 41 डी के अनुसार प्रदान की गई जुर्माने की शक्तियों का प्रयोग न करके प्रतिवादी संख्या 2 से 9 पर जुर्माना न

लगाना कानून में त्रुटिपूर्ण है, जिसे उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश में गलती से सही ठहराया है।

11. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के लिए पेश हो रहे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन ने यह तर्क दिया है कि जेसीसी और उच्च न्यायालय दोनों ने इस तथ्य को मान्यता दी है कि उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों और कार्यों का पूर्ण प्रत्यायोजन मृतक विजय मेहता को कर दिया था, और इस प्रकार, वे प्रबंध न्यासी द्वारा किए गए किसी भी कृत्य या अकृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, और इसलिए अधिनियम की धारा 41डी के प्रावधान के तहत जेसीसी द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

12. उन्होंने और भी उग्रता से जेसीसी द्वारा उन पर दंड न लगाने के निर्णय और आदेश में दर्ज किए गए निष्कर्षों और कारणों का समर्थन करने की मांग की है, जिसे उच्च न्यायालय ने भी सहमति प्रदान की है, जो कि न्यास डीड के क्लॉज 9 और 11(एच) के अनुसार है, जो न्यासीगण को अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन प्रबंधक न्यासी को करने की अनुमति देता है, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 2 से 9 ने मृतक विजय मेहता के पक्ष में किया है, जो कि न्यास के प्रबंधक न्यासी थे, और यह सब न्यास की दिनांक 30.8.2001 की प्रस्तावना के माध्यम से हुआ, जिस पर अपीलकर्ता ने भी हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने न्यास डीड के क्लॉज 9 और 11(एच) पर भी भारी निर्भरता व्यक्त की है, जो न्यासीगण को अन्य

किसी न्यासी के पक्ष में अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को सौंपने की क्षमता प्रदान करता है।

13. वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने कानूनी पक्ष को सिद्ध करने के लिए इस न्यायालय के शेख अब्दुल कयूम एवं अन्य बनाम मुल्ला अलीभाई एवं अन्य[(2)] के मामले में दिए गए निर्णय पर भी आधारित भरोसा व्यक्त किया। उन्होंने यह बताया कि न्यास डीड के उक्त खंड के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 से 9 न्यास के प्रबंध न्यासी को अपनी शक्तियाँ और कर्तव्य सौंपने के लिए सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि 30.8.2001 को आयोजित न्यास के संकल्प की बैठक के कार्यवृत्त से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता उस संकल्प की बैठक में उपस्थित थे। इसी आधार पर, जेसीसी ने यह सही ठहराया है कि अपीलकर्ता बैठक में उपस्थित थे और संकल्प वैध था।उन्होंने जेसीसी और उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेशों में दर्ज निष्कर्षों पर भी भरोसा व्यक्त किया है, जहाँ उन्होंने यह माना है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 9 द्वारा मृतक विजय मेहता के पक्ष में शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन उचित है, और उन पर जेसीसी और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा दंड नहीं लगाना भी उचित है, क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा आरोपों के संदर्भ में उनकी दोषसिद्धि साबित नहीं की गई है। इसलिए, उनका यह कहना है कि ये कार्यवाहियाँ कानूनी और वैध हैं और इस न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

14. प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने निर्णय और आदेश में जेसीसी के निष्कर्षों पर और अधिनियम की धारा 41 डी के प्रावधानों पर भी मजबूत भरोसा व्यक्त किया है, यह कहते हुए कि जेसीसी ने प्रतिवादी संख्या 2 से 9 पर दंड न लगाकर अपनी विवेकाधीन शक्तियों का सही उपयोग किया है, जिसे उच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि जेसीसी द्वारा उक्त प्रतिवादियों के खिलाफ दर्ज किये गए निष्कर्ष ऐसे नहीं हैं कि अधिनियम की धारा 41 डी के अंतर्गत प्रदत्त दंड लगाने के लिए उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो। इसके अलावा, उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि उपरोक्त प्रतिवादियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप अधिनियम की धारा 41 डी के अंतर्गत जेसीसी द्वारा उन पर दंड लगाने की शक्ति के प्रयोग की जरूरत को साबित नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रावधानों के अनुसार दंड लगाने से प्रतिवादी संख्या 2 से 9 पर गंभीर परिणाम उत्पन्न होंगे, और इसी कारण से, इसका कठोरता से अनुपालन नहीं किया जाना चाहिए।

15. इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी दावा किया है कि अपीलकर्ता 30.8.2001 को आयोजित न्यास की बैठक में ट्रस्टियों में से एक थीं, जिन्होंने प्रबंधकीय न्यासी के पक्ष में अपनी शक्तियाँ और कार्यभार सौंप दिया था। उन्होंने जेसीसी के सामने गवाही देने के लिए गवाह बॉक्स में प्रवेश भी नहीं किया, ताकि बैठक में अपनी भागीदारी और उस तिथि को पारित किए गए प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर का खंडन कर सकें, जिसमें

उन्होंने मृत विजय मेहता के पक्ष में अपनी शक्तियाँ और कार्यभार सौंपे थे। इसके अलावा, जब जेसीसी ने उससे न्यास के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा, तब उसने वो रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किये। इसी एक कारण से, जेसीसी को प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के खिलाफ दायर की गई अपीलकर्ता की अर्जी को खारिज कर देना चाहिए था।

16. उपरोक्त उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी जोरदार ढंग से तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता ने उनके समक्ष शिकायत दर्ज करके जेसीसी के प्राधिकरण की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है, जबकि वह स्वयं शक्तियों और कार्यों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल थी। मृतक विजय मेहता| इस प्रकार, वह यह तर्क नहीं दे सकती कि न्यासी-प्रतिवादी संख्या द्वारा उक्त विजय मेहता को शक्तियों और कर्तव्यों का प्रतिनिधिमंडल दिया गया है। 2 से 9, न्यास के दिनांक 30.8.2001 के संकल्प के अनुसार एक अमान्य प्रतिनिधिमंडल है। इसलिए, प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि जेसीसी का दृष्टिकोण, जिस पर उच्च न्यायालय ने सही सहमति जताई है, कानूनी और वैध है। इसलिए, इस मामले में लागू फैसले और आदेश के खिलाफ अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा विचार और हस्तक्षेप के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है। अन्य उत्तरदाताओं की ओर से अन्य विद्वान वकीलों ने भी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की दलील को अपनाया है, जिन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 से 9 की ओर से बहस की है।

17. पार्टियों की ओर से उत्थापित उपर्युक्त प्रतिस्पर्धी कानूनी तर्कों के संदर्भ में, हमने जेसीसी के विवादित निर्णयों और आदेशों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेशों की भी जांच की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उत्पन्न होगा की नहीं। इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सावधानीपूर्ण जांच और जेसीसी तथा उच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेशों के गहन अध्ययन के बाद, हमारा मत है कि कानून का कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इस मामले में, जहां न्याय का कोई अन्यायपूर्ण उल्लंघन नहीं हुआ है, वहां हमारा हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। ऊपर उल्लिखित निष्कर्षों के समर्थन में, हम नीचे अपने कारण अभिलिखित करते हैं:-

यह एक अविवादित तथ्य है कि लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल न्यास अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत एक सार्वजनिक पंजीकृत न्यास है। न्यास की न्यास डीड के धारा 9 और 11(एच) जो नीचे उद्धृत किए गए हैं, वे न्यास के ट्रस्टियों द्वारा शक्तियों और कार्यों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करते हैं। इसके अंतर्गत न्यासीगण अपने में से एक या अधिक मौजूदा न्यासी को नियुक्त कर सकते हैं ताकि वे न्यासीगण की उन सभी शक्तियों और कार्यों का निर्वहन करें जो वे उचित और अनुरूप समझें। न्यास डीड के प्रासंगिक खंड इस प्रकार पढ़े जाते हैं:-

"9. वर्तमान समय के न्यासी, अपने बीच से एक या अधिक ट्रस्टियों को प्रबंधन न्यासी या प्रबंधन ट्रस्टियों के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, ट्रस्टियों की उन सभी या कुछ विशेष शक्तियों और प्राधिकरणों के साथ, जो वे उचित समझें, और समय-समय पर किसी भी ऐसी शक्तियों और प्राधिकरणों को वापस भी ले सकते हैं।

11. वर्तमान में न्यासीगण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और इस द्वारा या कानून द्वारा प्रदत्त या समझे गए या न्यासीगण में वेस्टेड किसी भी शक्तियों की सामान्यता को प्रभावित किए बिना, निम्नलिखित शक्तियां और अधिकार स्पष्ट रूप से न्यासीगण को प्रदान किए जाते हैं, अर्थात्:

(ज) प्राधिकार की शक्ति से या अन्यथा किसी न्यासी या न्यासी या अन्य व्यक्तियों को, चाहे कोई भी शक्ति कानून द्वारा निहित हो या कानून द्वारा प्रदत्त हो या इन उपहारों द्वारा ट्रस्टियों में निहित हो, सौंपना, लेकिन ट्रस्टियों को कृत्यों के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। या किसी व्यक्ति या व्यक्ति की चूक, लेकिन केवल उनके अपने संबंधित कार्यों और चूक के लिए;"

18. जेसीसी के निष्कर्ष पार्टियों द्वारा रिकॉर्ड पर पेश की गई दलीलों और भौतिक साक्ष्यों और दिनांक 30.8.2001 के संकल्प पर आधारित हैं, जिसमें न्यास के अपीलकर्ता सहित न्यासियों, प्रतिवादी संख्या 2 से 9 तक ने अपनी शक्तियां और कार्यों को मृतक विजय मेहता के प्रति सौंप दिया था न्यास के मामलों का प्रबंधन करने के लिए। प्रतिनिधि मृतक विजय मेहता को दी गई शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में दिनांक 30.08.2001 के संकल्प के प्रासंगिक पैराग्राफ 1 से 4 और 9 इस प्रकार पढ़ें: -

> "यह संकल्पित किया जाता है कि श्री विजय के. मेहता को न्यास के प्रबंधन और न्यास की समस्त गतिविधियों के लिए पूर्ण और एकमात्र अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए, जो चैरिटेबल ट्रस्टों पर लागू होने वाले कानून की विधिक प्रावधानों के अनुरूप होगा और जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं: -"
>
> 1. लीलावती अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुंबई के सभी प्रकार के मामलों जैसे वित्तीय, तकनीकी, प्रशासनिक और प्रबंधन का संपूर्ण रूप से प्रबंधन करना।
> 2. लीलावती कीर्तिलाल मेहता चैरिटेबल अस्पताल, पालनपुर के समस्त मामलों का प्रबंधन करना, जिसमें वित्तीय, तकनीकी, प्रशासनिक और अस्पताल का संचालन शामिल है।

3. किसी भी एजेंसी, बैंकर्स या कार्यकारी अधिकारियों को न्यास की गतिविधियों और कार्यों को संपादित करने के लिए नियुक्त करने और उन्हें अधिकार प्रदान करने के साथ-साथ न्यास की ओर से किसी भी समझौते, दस्तावेज या करारों को क्रियान्वित करने हेतु न्यासीयों की नियुक्ति करना।

4. धन और/या चल अथवा अचल संपत्ति के दान को न्यासीगण जिन नियमों और शर्तों को उचित समझें, उनके अनुसार स्वीकार करना, बशर्ते कि ये शर्तें इस न्यास के मूल प्रस्तावों के विरुद्ध न हों। हालांकि, ऐसा कोई भी दान जिसकी शर्तों में न्यास के नाम और इसकी मौजूदा गतिविधियों में परिवर्तन की मांग हो, स्वीकार नहीं किया जाएगा।

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

"9. न्यास के कोष या उसकी आय से, उनके सभी अथवा किसी भी उद्देश्य के लिए, ऐसे सार्वजनिक परोपकारी संस्थाओं को दान या अंशदान प्रदान करना।"

19. अतः, न्यास डीड के खंड 9 और 11 (एच) की सूक्ष्म परीक्षा से स्पष्ट होता है कि ट्रस्टियों द्वारा अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का

प्रतिनिधित्व दूसरे न्यासी या ट्रस्टियों को सौंपने की व्यापक संभावना मौजूद है। इसी के प्रमाण के तौर पर, उत्तरदाताओं की ओर से माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता ने जे.पी. श्रीवास्तव एंड संस (प्रा.) लिमिटेड बनाम ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड[(3)] के मामले में इस अदालत के निर्णय पर ठोस आधारित विश्वास व्यक्त किया है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है:-

> "29. इसलिए, यद्यपि नियमतः ट्रस्टियों को अपने कार्यों को सामूहिक रूप से करना अनिवार्य है, यह सिद्धांत कुछ विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप होता है, जब एक न्यासी अन्य सभी के लिए कार्य कर सकता है: (1) जहां न्यास डीड में एक या अधिक ट्रस्टियों या बहुमत द्वारा ट्रस्टों के निष्पादन की अनुमति हो; (2) जहां सह-ट्रस्टियों द्वारा किसी कार्य के लिए व्यक्त मंजूरी या स्वीकृति प्रदान की गई हो; (3) जहां शक्तियों का प्रत्यायोजन आवश्यक हो; (4) जहां सक्षम लाभार्थी प्रत्यायोजन के लिए सहमति देते हों; (5) जहां व्यावसायिक नियमित प्रक्रिया के अनुसार किसी सह-न्यासी को प्रत्यायोजन सौंपा जाता हो; (6) जहां सह-न्यासी सिर्फ उन निर्णयों को प्रभावी बनाने का कार्य करता है जो सभी ट्रस्टियों ने मिलकर लिए हों।"
>
> (इस न्यायालय द्वारा विशेष बल दिया गया)

20. जेसीसी ने न्यास के 30.8.2001 के संकल्प के आधार पर अपनी तथ्यात्मक निष्कर्ष सही रूप में दर्ज किया है, यह पाया गया कि

अपीलकर्ता उक्त संकल्प के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे और प्रतिवादी संख्या 2 से 9 की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह सही रूप से संकेत किया है कि अपीलकर्ता 30.8.2001 की बैठक में मौजूद थे, जो कि बैठक के कार्यवृत्त से स्पष्ट है। इसी तथ्य का उल्लेख जेसीसी ने भी अपने 25.9.2009 के आदेश में किया है। इस न्यायालय में यह तथ्य कि अपीलकर्ता के हस्ताक्षर संकल्प पर गंभीरता से विवादित हैं, उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जेसीसी द्वारा रिकॉर्ड के आधार पर दर्ज की गई तथ्यात्मक खोज को उच्च न्यायालय द्वारा भी सही ठहराया गया है और इस अपील में उस निष्कर्ष को गलत नहीं कहा जा सकता क्योंकि अपीलकर्ता ने जेसीसी के समक्ष गवाही देने के लिए गवाह कटघरे में प्रवेश नहीं किया था ताकि उसके हस्ताक्षर की सत्यता और संकल्प की मिनट्स बुक की सटीकता का खंडन किया जा सके। इसके अलावा, जेसीसी के समक्ष अपीलकर्ता के पति, जो मूल प्रतिवादी संख्या 10 थे, ने प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन करने हेतु गवाह कटघरे में प्रवेश किया, परंतु उन्होंने जेसीसी के समक्ष हलफनामा साक्ष्य प्रस्तुत करने के अतिरिक्त कोई अन्य सबूत पेश नहीं किए। न्यास की मिनट्स बुक और वर्ष 2000 से 2007 तक के संकल्प तथा इस मामले में प्रस्तुत अतिरिक्त संकलन पेपर बुक को इस अदालत ने रिकॉर्ड में नहीं लिया है, क्योंकि उनका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन द्वारा, प्रतिवादी संख्या 2 से 9 की ओर से, यह कहते हुए सही विरोध किया गया है कि ये दस्तावेज जेसीसी के समक्ष सबूत के रूप में प्रस्तुत

नहीं किए गए थे, और इसलिए इस अपील में इन्हें विचाराधीन नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 से 9 की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह स्पष्ट किया है कि जेसीसी के समक्ष मूल प्रतिवादी संख्या 10 श्री किशोर मेहता को उन वित्तीय लेनदेनों की कोई जानकारी नहीं थी, जिनके संबंध में उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं क्योंकि वित्तीय लेनदेनों को केवल स्वर्गीय श्री विजय मेहता द्वारा ही संभाला जाता था।

21. इसके अलावा, अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा 1882 के अधिनियम की धारा 46 और 47 पर निर्भरता सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास पर लागू नहीं होती है, जैसा कि थायरम्मल बनाम कनकम्मल और अन्य[(4)] के मामले में इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था, जो इस प्रकार पढ़ता है :-

> "15. पत्थर के शिलालेख की सामग्री स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि मालिक ने संपत्ति को "धर्मचत्र" के रूप में उपयोग करने के लिए समर्पित किया है, जिसका अर्थ है त्यागराज मंदिर आने वाले यात्रियों और तीर्थयात्रियों के लिए एक विश्राम स्थल। सख्त कानूनी अर्थों में ऐसा समर्पण न तो "उपहार" है जैसा कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में समझा जाता है जिसके लिए दान की गई संपत्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता होती है और न ही यह "न्यास" है। जैसा कि इसकी प्रस्तावना और सामग्री से

स्पष्ट है, भारतीय न्यास अधिनियम केवल निजी ट्रस्टों पर लागू होता है, सार्वजनिक ट्रस्टों पर नहीं। किसी हिंदू द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया समर्पण सख्त कानूनी अर्थों में न तो "उपहार" है और न ही "न्यास" है..."

अतः, प्रतिवादी संख्या 2 से 9 तक और अपीलकर्ता द्वारा न्यास के प्रबंधक न्यासी, स्वर्गीय विजय मेहता के पक्ष में सभी शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन, कानून के अनुसार अनुमत है क्योंकि न्यास के इंस्ट्रुमेंट में इसका प्रावधान है।

22. तथ्यों के निष्कर्षों को जेसीसी द्वारा पैराग्राफ 255 में निर्णय और आदेश में दर्ज किया गया है, जो इस प्रकार से है: -

"255. आवेदन में सभी ट्रस्टियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, सभी आरोपों के संबंध में विशेष आरोप केवल प्रतिवादी संख्या 9 पर हैं। आवेदन के पैराग्राफ संख्या 10, 27, 2 आदि का आशय यह है कि वह न्यास के मामलों का गलत प्रबंधन कर रहा है। वह न्यास की गतिविधियों को अकेले ही संचालित करने का प्रयास कर रहा है। श्री दुष्यन्त मेहता और श्री सुरेश मोटवानी के नाम का बार-बार प्रतिवादी संख्या 9 के साथियों या सहयोगियों

के रूप में उल्लेख किया गया है। बाकी ट्रस्टियों पर मिलीभगत और सांठगांठ के आरोप हैं। लेकिन आरोप सामान्य प्रकृति के हैं। वे अस्पष्ट हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 8 तक के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाए गए हैं।"

इस मामले में जेसीसी के आदेश की जो टाइप की गई प्रति पेश की गई है, वह सही नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जेसीसी के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है:

"265. संक्षेप में, मेरा निर्णय है कि आरोप 1 से 8 प्रतिवादी संख्या 9 के खिलाफ सिद्ध होते हैं। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के विरुद्ध उत्तरदायी ठहराए गए लेन-देन के लिए कोई प्रमाण नहीं है।"

जेसीसी के आदेश के उपरोक्त उद्धृत पैराग्राफों को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के खिलाफ कोई संलिप्तता सिद्ध नहीं हुई है, क्योंकि जेसीसी ने पाया है कि उन्हें आरोपित लेन-देन के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, जिसका अर्थ है कि जेसीसी ने यह निर्णय दिया है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के खिलाफ दोषारोपण स्थापित नहीं होता है। इसके अलावा, जेसीसी ने अधिनियम की धारा 41 डी के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग

जिम्मेदार तरीके से किया है, मनमाने तरीके से नहीं, जैसा कि उनके निष्कर्ष के पैराग्राफ 261 और 262 को पढ़ने से देखा जा सकता है, जो इस प्रकार है:

> "261. निष्कर्ष के तौर पर, मुझे प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उन्हें कथित लेन-देन से सीधे जोड़ा जा सके। प्रतिवादी संख्या 2,3,4 और 7 ने स्वीकार किया है कि वे बोर्ड ऑफ न्यासीज में वर्ष 2004 में, बहुत बाद में शामिल हुए थे। उन्हें न्यासी के रूप में शामिल होने से पहले, अतीत में किए गए कार्यों के लिए दोषी ठहराना गलत होगा।
>
> 262. ये प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 9 पर अंध विश्वास रखने में लापरवाही बरत सकते हैं। उन्हें न्यास मामलों में पूरी छूट देना गलत था। वे प्रतिवादी संख्या 9 पर अत्यधिक निर्भर थे। संभवतः यह तथ्य कि वह मेहता परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, और जब से उन्होंने प्रबंधक न्यासी के रूप में पदभार संभाला, अस्पताल ने धन और प्रसिद्धि दोनों अर्जित की है, ये तथ्य उनके मन में गहराई से बैठ गए होंगे, जिसके चलते उन्होंने उन पर पूर्ण विश्वास और निर्भरता जताई। इसके लिए उनकी आलोचना होनी चाहिए। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 9 पर उनकी अत्यधिक निर्भरता, लापरवाही

और रुचि की कमी, उनके पद से हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

जेसीसी के उक्त निष्कर्षों और टिप्पणियों की पुष्टि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने निर्णय में की है, जो इस प्रकार है:

" ... जॉइंट चैरिटी कमीशन ने प्रतिवादी संख्या 9 के निष्कासन के लिए आदेश देने के लिए कारण बताए हैं।

संयुक्त चैरिटी आयुक्त द्वारा दिए गए कारणों को किसी भी रूप में अनुचित या असंभव नहीं कहा जा सकता है। हमारी राय में, इसलिए यह मानते हुए कि आदेश संयुक्त चैरिटी आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है और आदेश देने के लिए उनके द्वारा दिए गए कारण भी संभव और विश्वसनीय हैं। माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश में हस्तक्षेप न करने का निर्णय उचित था। हमें यह भी जानकारी दी गई है कि जब माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका में आदेश की वैधता की जांच की, तो प्रतिवादी नंबर 9 के खिलाफ आदेश में दर्ज की गई निष्कर्षों को उनके द्वारा संबंधित न्यायालय में दायर की गई अपील में स्थगित कर दिया गया था।"

23. इसलिए, यह तथ्य कि अपीलकर्ता ने गवाही के लिए कटघरे में प्रवेश नहीं किया और यह भी कि प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के खिलाफ लगाए गए समान आरोप उनके खिलाफ भी जेसीसी के समक्ष लंबित थे, क्योंकि वह दिनांक 30.8.2001 के संकल्प की हस्ताक्षरकर्ता थीं, जिसमें उन्होंने मृतक विजय मेहता को अपनी शक्तियाँ और कार्य सौंपे थे, जेसीसी को मूल प्रतिवादी संख्या 10 का साक्ष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए था और न ही अपने आदेश में आरोपों पर निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए था। इसके अलावा, उन्होंने यह सही ठहराया है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 9 का दोष सिद्ध नहीं हुआ है और यह भी माना है कि उन्होंने केवल मृतक विजय मेहता, प्रबंध न्यासी को अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रतिनिधित्व सौंप कर लापरवाही बरती है, परंतु उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं क्योंकि वे कथित लेन-देन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, अतः उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई सांठगांठ नहीं है। जेसीसी द्वारा दिए गए इस निष्कर्ष की नींव रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और साक्ष्यों पर रखी गई है, इसलिए, उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से प्रतिवादी संख्या 2 से 9 को दायित्वों से मुक्त कर दिया है और अधिनियम की धारा 41 डी के तहत कोई दंड नहीं लगाया है, क्योंकि उनका निर्णय उचित और न्यायसंगत था। अतः, उच्च न्यायालय ने भी जेसीसी के निष्कर्षों के साथ सहमति जताई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 से 9 को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया गया है, और इसके लिए एक तर्कसंगत निर्णय और आदेश दिया गया है।

24. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जिन मामलों पर निर्भर किया गया है, जैसे कि शेख अब्दुल कयूम और अन्य बनाम मुल्ला अलीभाई और अन्य(सुप्रा), जे.पी. श्रीवास्तव एंड संस (पी) लिमिटेड बनाम ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड (सुप्रा), और डी. गोपालस्वामी मुदलियार बनाम सुब्रमण्यम पिल्लई और अन्य [(5)], वर्तमान मामले की स्थिति से असंगत हैं क्योंकि वे अपीलकर्ता के मामले का समर्थन नहीं करते हैं। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने लाला मन मोहन दास बनाम जानकी प्रसाद और अन्य (सुप्रा) के मामले पर भी दृढ़ता से निर्भर किया है। प्रिवी काउंसिल के निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है: -

> "सह-ट्रस्टियों के मामले में, कार्यालय एक संयुक्त स्वरूप का होता है। जब न्यास का प्रशासन सह-ट्रस्टियों को सौंपा जाता है, तो वे सभी मिलकर एक सामूहिक न्यासी का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार उन्हें उनके कार्यालय के कर्तव्यों को उनकी संयुक्त क्षमता में निभाना चाहिए। अक्सर कई ट्रस्टियों में से किसी एक को कार्यवाहक न्यासी के तौर पर संदर्भित किया जाना आम बात है, लेकिन न्यायालय ऐसे किसी भेदभाव को नहीं मानता है; कानून की दृष्टि में पद स्वीकार करने वाले सभी लोग कार्यवाहक ट्रस्टियों के रूप में माने जाते हैं। यदि कोई शामिल होने से इनकार करता है या असमर्थ है, तो अन्य ट्रस्टियों के लिए उसके

बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है, और ऐसी स्थिति में न्यास का प्रशासन न्यायालय के हाथ में होना चाहिए|हालांकि, यदि किसी न्यासी का कार्य सह-न्यासी की मंजूरी और अनुमोदन के साथ किया गया है, तो इसे दोनों का कार्य माना जा सकता है। लेकिन ऐसी मंजूरी या अनुमोदन को सख्ती से साबित करना होगा।"

हालाँकि, रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्यों और साक्ष्यों को देखते हुए उक्त निर्णय को इस मामले की वास्तविक स्थिति पर लागू नहीं किया जा सकता है।

25. उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश और जेसीसी के आदेश कानूनी और वैध हैं और इस न्यायालय द्वारा अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अपील खारिज की जाती है.

26. चूंकि मृतक विजय मेहता के खिलाफ लगाए गए निष्कर्षों और दंडों के खिलाफ अपील सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित है, जिस पर उनके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है और इसलिए, सिविल कोर्ट को टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना उक्त मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करने की आवश्यकता है। और इस निर्णय में हमारे द्वारा बताए गए कारण। हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि उक्त अपील की जांच कानूनी

आधारों और उसमें दिए गए तर्कों की पृष्ठभूमि में स्वतंत्र रूप से की जानी चाहिए और कानून के अनुसार उसका निपटान किया जाना चाहिए।

कल्पना के.त्रिपाठी

अपील खारिज की गई।

(1) एआईआर. (32) 1945 प्रिवी कौंसिल 23

(2) (1963) 3 एससीआर 623

(3) (2005) 1 एससीआर 172

(4) (2005) 1 एससीआर 457

(5) (1942) 1 एम्एलजे 272

यह अनुवाद अर्तिफिसिअल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक **अधिवक्ता नाजिश रशीद** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।